

TODAY WEATHER



DAY

37°

Hi

NIGHT

26°

Low

संक्षेप

माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही प्रभावित, बैटरी कार सेवा स्थगित

रियासी। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए बनाया गया नया हिमकोटि मार्ग सोमवार को तेज बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसका असर मंगलवार को भी दिखा। रास्ते में मिट्टी और पत्थरों से श्रद्धालुओं को आने-जाने में समस्या हुई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बैटरी कार की सेवा स्थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी पुलिस और प्रशासन की मदद से मार्ग को सुचारु कर रहे हैं। नए मार्ग पर विपदा आने के बाद तीर्थ यात्रियों को पुराने मार्ग पर भेज दिया गया है। यहां से मंदिर तक के लिए यात्रा जारी है। नए हिमकोटि मार्ग पर सत्या व्यू प्वाइंट के निकट मार्ग पर भूस्खलन तब हुआ, जब क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की आवाजाही नहीं थी। इससे बड़ा हादसा टल गया। भूस्खलन का मलबा 30 फीट से अधिक मार्ग पर फेला हुआ है। मार्ग की सफाई के बाद बैटरी कार सेवा को बहाल किया जाएगा। हिमकोटि मार्ग पर भूस्खलन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें श्रद्धालु कीचड़ और मलबे के बीच से निकलते नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी 5 दिन से स्थगित है। इसके अलावा वैष्णो देवी के भवन से भैरव घाटी तक केबल कार की सेवा भी रोक दी गई है। यहां मार्ग पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है।

महाराष्ट्र में 5 महीने में 30,000 से अधिक लोग लापता, मुंबई में सबसे ज्यादा

मुंबई। महाराष्ट्र में अचानक लापता होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 महीने में पूरे राज्य में 30,000 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। पुलिस के आंकड़ों के हवाले से पता चला है कि लापता होने वालों में राज्य में मुंबई सबसे आगे है, जहां जनवरी से मई के बीच में 3,475 लोग गायब हुए हैं, जो कुल मामलों का 10 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़े पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पिछले 5 महीने में 30,113 लोग, यानी रोजाना औसतन 200 लोग गायब हो रहे हैं। लापता लोगों के मामले में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर ठाणे हैं, जहां 5 महीने में 2,003 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यहां अक्सर लापता व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है। इसके बाद अहिल्याबाई नगर है, जो आबादी में बेहद कम है। यहां 1,411 गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक गुमशुदगी के मामले मुंबई, ठाणे और अहिल्याबाई नगर के बाद पुणे और नासिक ग्रामीण में हैं। पुणे में 1,364 और नासिक में 1,338 लापता व्यक्ति हैं। ये राज्य के शीर्ष-5 शहर हैं, जहां लापता व्यक्तियों की संख्या अधिक है। लापता कुल 30,113 लोगों में 12,467 पुरुष और 17,646 महिलाएं हैं। इसमें नाबालिग शामिल नहीं है क्योंकि उनको अपहरण में दर्ज किया जाता है। फरवरी में लापता लोगों की संख्या कम है, जबकि मार्च में 17 प्रतिशत बढ़ी है। लापता लोगों में खुद से घर छोड़ने वाले, मानसिक बीमारी, मानव तस्करी और प्राकृतिक आपदा में गायब लोग शामिल हैं। इनका पता लगाने के लिए पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है। साथ ही सार्वजनिक सहयोग को भी बढ़ा रही है।

आर्यावर्त क्रांति

हिंदी दैनिक

ऑपरेशन सिंदूर से दिखा दिया, भारतीयों का खून बहाने वालों के ठिकाने सुरक्षित नहीं पीएमकी दो टूक

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया ने हाल ही में ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिन्दूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत, देशहित में जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर कहा कि हमने इतने दशक



बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है, बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देती है। इसका सबसे अधिक लाभ पिछड़ों को हो रहा है। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य, हर पहलू में आगे रहना है। आज देश, इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी को लेकर कहा कि आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना, जिसने न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को नए मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो

मुलाकात आज भी उतनी की प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले वो मुलाकात, सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के स्रोत की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्रीनारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। भारत की विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, तो कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाता है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में

समाज सुधारों को गति देता है।

‘हमारी कोशिश में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा’

उन्होंने कहा कि अभी हालही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इससे पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए ‘वन वर्ल्ड, वन हेल्थ’ जैसे पहल की है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को लीड कर रहा है। 2023 में जब भारत ने G20 समिट को लीड किया था, तब थीम रखी थी वन अर्थ, वन पेमिली, वन भूपुर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जुड़ी हुई है।

हिंदी को 100% राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए, भाषा विवाद के बीच अबू आजम की मांग

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा कि मराठी पहली भाषा है, लोग अंग्रेजी के पीछे भागते हैं क्योंकि वे ‘गुलाम’ हैं, इसलिए यह दूसरी भाषा है। मैं बार-बार दोहराता हूँ कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। संसद में एक समिति है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जाती है और केंद्र सरकार के सभी काम भी हिंदी में होते हैं। कुछ लोग राजनीतिक करना चाहते हैं... हिंदी को 100% राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जानी चाहिए। अगर मैं असम जाऊँ तो क्या मुझे असमिया



सीखना चाहिए?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार रात घोषणा की कि राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मुला लागू करने पर अंतिम निर्णय लेखकों, भाषा विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। यह कदम स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने के सरकार के फैसले के व्यापक विरोध के बीच उठाया गया है।

ईरान पर अमेरिकी बमबारी खुली आक्रामकता है, जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली, एजेंसी। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ईरान पर हाल ही में अमेरिका द्वारा की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल अब पश्चिम एशिया में खून-खराबे और आतंकवाद का केंद्र बन गया है, जिसे अमेरिका से पूरा संरक्षण मिल रहा है। महमूद असद मदनी ने कहा कि अमेरिका ने अपनी आक्रामक नीतियों के माध्यम से लगातार दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और पश्चिम एशिया में उसकी उपस्थिति एक उपचारात्मक शक्ति से जहर के स्रोत में बदल गई है।

मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि जब तक पश्चिम एशियाई देश एकजुट होकर अपनी धरती से अमेरिकी ठिकानों को नहीं हटाते, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा पूरा क्षेत्र इन शैतानी साजिशों का शिकार होता रहेगा, जैसा कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया के साथ हुआ और अब ईरान के खिलाफ भी यही धिनीना खेल दोहराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी शक्तिशाली देश को



अपने विवेक से दुनिया में कहीं भी सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। इस तरह की हरकतें न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि वैश्विक अविश्वास, घृणा और अस्थिरता को भी बढ़ावा देती हैं। मानवता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और कोई भी कदम जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, मानवाधिकारों को रौंदता है, और वैश्विक शांति को खतरों में डालता है, उसे अस्वीकार्य माना जाना चाहिए। इसका मुकाबला केवल कूटनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि दृढ़ कार्रवाई से किया जाना चाहिए।

अविश्वास, घृणा और अस्थिरता को भी बढ़ावा देती हैं। मानवता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और कोई भी कदम जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, मानवाधिकारों को रौंदता है, और वैश्विक शांति को खतरों में डालता है, उसे अस्वीकार्य माना जाना चाहिए। इसका मुकाबला केवल कूटनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि दृढ़ कार्रवाई से किया जाना चाहिए।

इस्राइल से लौटे 594 भारतीय नागरिक, MEA बोला– विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता

नई दिल्ली। इस्राइल-ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को इस्राइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के तीन विमान नई दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161, दूसरे विमान में 165 और तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक आए। भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) पाबित्रा मांगेरीटा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने स्वागत किया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंधु का इस्राइल चरण 23 जून 2025 को शुरू हुआ। इसमें जॉर्डन से 161 भारतीय नागरिकों का पहला जलथा स्वदेश लाया गया। इसके बाद वायुसेना का सी-17 विमान इस्राइल से 165 यात्रियों को वापस लेकर आया। वहीं मंगलवार दोपहर को तीसरा विमान 268 नागरिकों को लेकर भारत आया। इससे पहले मशहद से नई दिल्ली पहुंचे एक विशेष विमान से 292 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया जा चुका है।



जून 2025 को शुरू हुआ। इसमें जॉर्डन से 161 भारतीय नागरिकों का पहला जलथा स्वदेश लाया गया। इसके बाद वायुसेना का सी-17 विमान इस्राइल से 165 यात्रियों को वापस लेकर आया। वहीं मंगलवार दोपहर को तीसरा विमान 268 नागरिकों को लेकर भारत आया। इससे पहले मशहद से नई दिल्ली पहुंचे एक विशेष विमान से 292 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया जा चुका है।

भारतीय नागरिकों ने जताई खुशी

इस्राइल से लौटे बुजुर्ग दंपती त्रिव्यंबक कोली ने कहा कि मुझे इस्राइल में डेढ़ महीना हो गया था। वहां अचानक स्थिति बिगड़ गई। हम दिन के किसी भी समय विस्फोटों की आवाज सुन सकते थे। हम डर गए थे। अब हम वापस आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के बहुत आभारी हैं। हम अपने बेटे के नवजात शिशु से मिलने वहां गए थे। वे इस्राइल में ही रहेंगे। वे वापस नहीं

आएंगे। हम वापस आ गए हैं। स्थिति अभी भी बिगड़ रही है। उनकी पत्नी कहती हैं कि हमने आसमान में बम (मिसाइल) देखे। उनमें से छह हमारे सिर के ऊपर से गुजरे। जब हमने यह देखा तो हम छिप गए थे। हम प्रधानमंत्री मोदी के बहुत आभारी हैं।

सरकार का धन्यवाद

एक भारतीय ने कहा कि हमें वापस घर लाने के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम भारतीय दूतावास से बहुत मदद मिली। मैं भारत सरकार और भारतीय वायु सेना का आभारी हूँ। भारतीय दूतावास और भारत सरकार ने निकासी प्रक्रिया के दौरान हमारी बहुत मदद की। जब हम इस्राइल में अपने घर से निकले, तब भी हमें सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे थे।

जज शेखर यादव के खिलाफ होगा एक्शन ? कहां तक पहुंची महाभियोग मामले में MPs के सिग्नेचर की जांच

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर वो मुश्किल में फंस गए हैं। कार्यक्रम में उनकी कही गई बातों के चलते राज्यसभा के 54 सांसदों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था। विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव संसद के प्रोसीजर नियम के तहत अटक हुआ है। ये मामला अभी भी राज्यसभा के सभापति के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया तकनीकी अड़चनों में फंसी हुई है।

जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में 54 सांसदों ने महाभियोग का नोटिस दिया था, इसे मंजूर करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर सही



होने चाहिए थे, लेकिन 44 सांसदों के हस्ताक्षरों का ही वैरिफिकेशन हुआ है। राज्यसभा सचिवालय ने मार्च और मई में सांसदों को ईमेल और फोन करके उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करने को कहा था। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 44 सांसदों ने ही अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। बाकी 10 सांसदों से 6 ने भी कहा है कि उन्होंने ने भी नोटिस पर साइन किए हैं। ऐसे में अभी तक 50 सांसदों ने महाभियोग पर साइन करने की बात कही है।

55 सांसदों के हस्ताक्षरों की जांच

न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा सचिवालय के तय प्रोटोकॉल के मुताबिक इस प्रस्ताव के साथ जमा 55 सांसदों के हस्ताक्षरों की विस्तृत जांच शुरू गई है। यह जांच तब शुरू हुई जब किसी सदस्य के हस्ताक्षर दो बार दर्ज होने की शिकायत मिली। संबंधित सांसद ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के समक्ष दोबारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

एक दिन में भर देंगे 3400 गड्डे दिल्ली की सड़कों को लेकर मंत्री परवेश वर्मा का बड़ा दावा

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को बारिश का ये लो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली के अंदर मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में मानसून अब कभी भी दस्तक दे सकता है। उससे पहले दिल्ली में गड्डे भरने का काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि हमारा कमिटमेंट दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़कें देने का है, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है, इसलिए पीडब्ल्यूडी सारे इंजीनियर्स और स्टाफ के साथ में और फुल फोर्स के साथ में हमने एक ही दिन में 3400 गड्डे भरने का बेड़ा उठाया है।

मंत्री परवेश वर्मा ने आगे जानकारी देते हुए कहा, 'सुबह 11



बजे तक हमने 50 प्रतिशत से ज्यादा गड्डे भर दिए हैं, शाम तक सारे गड्डे भर दिए जाएंगे, हमारी सरकार की जो पारदर्शिता है, जो कमिटमेंट है, कि हमें दिल्ली को अच्छी और वर्ल्ड क्लास सड़कें देनी

हैं। पहले दिल्ली में अच्छी सड़कें होती थीं। पहले जब दिल्ली से बाहर जाते थे तो पता होता था कि दिल्ली खत्म हो रही है और दिल्ली में आते हैं तो पता होता है कि दिल्ली शुरू हो गई है, दिल्ली में इतने गड्डे हैं। '

‘गड्डों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं’

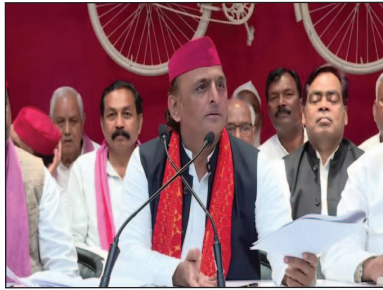
उन्होंने कहा कि पीछे की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में अच्छी सड़कें दें ताकि कोई भी एक्सीडेंट न हो। गड्डों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं तो वो भी न हो ये हमारा कमिटमेंट है। परवेश वर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर इस काम का जायजा लिया। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को बारिश की उम्मीद जताई है। सोमवार को कुछ बादल छाए रहे, ऐसे में आस लगाई जा रही है कि मानसून जल्दी ही दिल्ली में दस्तक दे सकता है और दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

कथावाचक की पिटाई : अखिलेश यादव बोले– भागवत कथा सबके लिए है जब सुन सकते हैं तो सुना क्यों नहीं सकते

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ वर्चस्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इटाली में कथावाचक की पिटाई कांड इन्हीं प्रभुत्वशाली लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर सभी लोग भागवत कथा सुन सकते हैं तो सुना क्यों नहीं सकते हैं? अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेंगा?

उन्होंने कहा कि प्रभुत्ववादी लोग ये घोषित करें कि पीडीए द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव मंगलवार को सपा मुख्यालय में कथावाचक की पिटाई मामले पर बोल रहे थे। बता दें कि इटाली में कथावाचक की जाति पृष्ठने के बाद पिटाई, बाल काटने और महिला के पैर पर नाक रगड़वाने का वीडियो



वायरल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार हृदयहीन और अलोकतांत्रिक है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारे घटनाएं नहीं होगी। अगर बाबा साहब के संविधान और प्रस्तावना के तहत ही फैसला लिया जाए तो गरीब और गांव में रहने वाले लोगों का और अल्पसंख्यकों का सम्मान होने लगे। भाजपा सरकार में पीडीए वर्ग के लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है।

वर्चस्ववादी ताकतें पीडीए का अपमान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए का कोई व्यक्ति मंदिर चला जाए तो ये उसे गंगाजल से धोते हैं। वर्चस्ववादी लोगों को सरकार का आशीर्वाद है जिसके कारण वो लोग ऐसा कर रहे हैं। समाज में

समानता और सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी।

कथावाचकों का किया सम्मान

वहीं, सपा कार्यालय में पीडित कथावाचकों को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। उन्होंने 21-21 हजार रुपये की धनराशि कथावाचकों को दी। वहीं, 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा समाजवादी पार्टी की ओर से की गई।

क्या है ‘पंप एंड डंप’ स्कैम, जिससे मिनटों में डूब जाती है निवेशकों की मेहनत की कमाई?

‘पंप एंड डंप’ स्कैम में ज्यादातर पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल होता है . पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे ₹1, ₹2 या ₹5 . इन शेयरों को ऑपरेट करना आसान होता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है और थोड़ी सी खरीदारी से भी इनकी कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है .



कुछ दिन पहले शेयर बाजार में निवेशकों की मेहनत की कमाई को लूटने वाले ठगों पर सेबी (SEBI) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद, मुंबई और गुरुग्राम में एक साथ छापेमारी कर सेबी ने ₹300 करोड़ के ‘पंप एंड डंप’ स्कैम का पर्दाफाश किया है। इस घोटाले में 15 से 20 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें कुछ लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स ने बनाया था। ये ठग यूट्यूब, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस के जरिए निवेशकों को झांसा देते थे। आइए, समझते हैं कि आखिर ये ‘पंप एंड डंप’ स्कैम है क्या, कैसे काम करता है

क्या है ‘पंप एंड डंप’ स्कैम

‘पंप एंड डंप’ एक ऐसा घोटाला है, जिसमें ठग शेयर बाजार में छोटे-मोटे या पेनी स्टॉक्स की कीमतों को पहले आसमान पर चढ़ाते हैं और फिर अचानक उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। इस दौरान आम निवेशक, जिन्हें रिटेल इनवेस्टर्स कहते हैं, फंस जाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई डूब जाती है। ये स्कैम सोशल मीडिया के जमाने में और खतरनाक हो गया है, क्योंकि ठग अब यूट्यूब, व्हाट्सऐप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए लाखों लोगों तक अपनी झूठी बातें

पहुंचा देते हैं।

इस स्कैम का तरीका बड़ा आसान लेकिन बेहद चालाकी भरा है। पहले ठग किसी कंपनी के शेयर को बहुत कम दाम पर खरीद लेते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर उस शेयर की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये शेयर जल्द ही चांद पर पहुंचेगा, इसमें निवेश करने से मोटा मुनाफा होगा। कई बार तो वो फर्जी खबरें भी फैलाते हैं, जैसे कि उस कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कोई बड़ी कंपनी उसे खरीदने वाली है। इन सबके लिए वो बड़े यूट्यूबर्स, इनफ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया स्टार्स का सहारा लेते हैं, जो अपने फॉलोवर्स को उस शेयर में पैसा लगाने की सलाह देते हैं।

जैसे ही लोग इन बातों में आकर उस शेयर को खरीदने लगते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत आसमान छूने लगती है। निवेशकों को लगता है कि जो उन्हें बताया गया, वो सच है और वो और पैसे उस शेयर में झोंक देते हैं। लेकिन असल में ये सब एक जाल होता है। जैसे ही शेयर की कीमत ठगों के मनमाफिक ऊंचाई पर पहुंचती है, वो अपने सारे शेयर बेच देते हैं, यानी ‘डंप’ कर देते हैं। इससे शेयर की कीमत अचानक धड़ाम से गिर जाती है, और आम निवेशक के हाथ में सिर्फ नुकसान रह जाता है।

कैसे काम करता है ये स्कैम?

‘पंप एंड डंप’ स्कैम का तरीका समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, एक कंपनी का शेयर ₹1 पर ट्रेड कर रहा है। ठग इस शेयर को बड़े पैमाने पर खरीद लेते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर इसके बारे में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कंपनी जल्द ही ₹50 तक जाएगी, क्योंकि इसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला है या कोई बड़ी कंपनी इसे खरीदने वाली है। लोग इन बातों पर भरोसा करके शेयर खरीदने लगते हैं। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है, शेयर की कीमत ₹10, ₹20, फिर ₹40 तक पहुंच जाती है।

निवेशकों को लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, और वो और शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही शेयर की कीमत ठगों के टारगेट तक पहुंचती है, वो अपने सारे शेयर बेच देते हैं। इससे मार्केट में शेयरों की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, और कीमत ₹2-3 तक गिर जाती है। जो निवेशक ऊंचे दाम पर शेयर खरीद चुके थे, उनके हाथ में सिर्फ घाटा रह जाता है। इस पूरे खेल में ठग मिनटों में करोड़ों कमा लेते हैं, और निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं।

इस स्कैम में कई बार निवेशक अपने शेयर बेच भी नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही ठग शेयर को ‘डंप’ करते हैं, शेयर का दाम तेजी से गिरने लगता है और वह अपने लोअर सर्किट पर पहुंच जाता है। लोअर सर्किट लगते ही शेयर में बिकवाली रुक जाती है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर महीनों तक हर दिन लोअर सर्किट पर अटक रहता है। निवेशकों को पता चल जाता है कि वे फंस चुके हैं, लेकिन उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता।

पेनी स्टॉक्स है ठगों का पसंदीदा हथियार

‘पंप एंड डंप’ स्कैम में ज्यादातर पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल होता है। पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे ₹1, ₹2 या ₹5। इन शेयरों को ऑपरेट करना आसान होता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है और थोड़ी सी खरीदारी से भी इनकी कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है। इसके अलावा, इन कंपनियों की जानकारी मार्केट में कम होती है, जिससे ठगों को फर्जी खबरें फैलाने का मौका मिल जाता है।

ईरान-इजराइल में सीजफायर के बाद अब हथियारों का बाजार बढ़ाने चला अमेरिका, नाटो समिट में डिफेंस बजट अहम मुद्दा

वॉशिंगटन, एंजेंसी। कहते हैं कि जंग अगर रुक भी जाए तो उसका मतलब शांति नहीं है। क्योंकि शांति जल्दी बहाल नहीं होती। उसमें काफी वक्त लग जाता है। इसीलिए शायद जंग के बाद शांति नहीं सीजफायर आता है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद अब सीजफायर हो गया। भारत-पाकिस्तान की तरह ही इसका भी ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पर मुश्किल ये है कि भले सीजफायर हो गया मगर जमीन पर हालात सामान्य नहीं।

इसी समय में शांति के पैरोकार बनकर खुद को पेश करने वाले ट्रंप अमेरिका हथियार के कारोबार की ओर हरा भरा करने में जुट गए हैं। ऐसे इशारे नीडरलैंड्स की राजधानी द हेग में 24-25 जून को होने वाली नाटो समिट में मिल रही है। जहां इसके सदस्य देशों के रक्षा बजट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अमेरिका की मंशा है कि नाटो देश अब अपनी GDP का 5 फीसदी हिस्सा डिफेंस पर खर्च करें यानी मौजूदा जो दायरा है, उस से ढाई गुना ज्यादा। इस प्रस्ताव ने यूरोपीय देशों के भीतर गंभीर मतभेद खड़े कर दिए हैं। कुछ देश ट्रंप की इस नई मांग के समर्थन में हैं, जबकि स्पेन जैसे देश इसका खुला विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है ये समझना कि नाटो समिट का एजेंडा क्या है, अमेरिका किस रणनीति के तहत ये दबाव बना रहा है और यूरोपीय देशों को इस पर आपत्ति क्यों है?

नाटो समिट: क्यों खास है ये बैठक?

नाटो (NATO) यानी नॉर्थ अटलंटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन के सदस्य देश हर साल मिलकर सुरक्षा और रक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार की समिट इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों के



डिफेंस खर्च पर बड़ा फैसला होने वाला है।

अभी तक नाटो देशों का लक्ष्य था कि वे अपनी GDP का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करें। लेकिन 2024 में भी लगभग एक-तिहाई सदस्य इस टारगेट को नहीं छू सके हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि यह टारगेट बढ़ाकर 5% किया जाए।

कौन कितना खर्च कर रहा है?

2024 के अनुमान के मुताबिक, अगर हम देखें कि नाटो देश अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा रक्षा पर खर्च कर रहे हैं, तो तस्वीर साफ है। कुछ देश खूब खर्च कर रहे हैं, तो कुछ अभी भी पीछे हैं। सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में पोलैंड सबसे आगे है, जो अपनी जीडीपी का 4.12% सिर्फ डिफेंस पर लगा रहा है। इसके बाद एस्टोनिया (3.43%) और अमेरिका (3.38%) का नंबर आता है। लातविया (3.15%) और ग्रीस (3.08%) भी तीन फीसदी से ऊपर हैं, यानी इन देशों ने सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया है।

वो देश जो रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं।

अब आते हैं उन देशों पर जो 2

फीसदी से ऊपर या उसके आसपास खर्च कर रहे हैं, जो कि नाटो की गाइडलाइन के मुताबिक ठीक-ठाक माने जा सकते हैं। इनमें लिथुआनिया, फिनलैंड, यूके, डेनमार्क, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, जर्मनी, स्वीडन, हंगरी, तुर्किये, फ्रांस, नीदरलैंड, अल्बानिया, मोटेनेग्रो और स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देश शामिल हैं। ये सभी 2 से 2।85% के बीच खर्च कर रहे हैं, यानी मानक को या तो पूरा कर चुके हैं या उससे थोड़ा आगे-पीछे हैं।

2 फीसदी से भी कम खर्च करने वाले देश

वहीं जिन देशों की डिफेंस पर खर्च की हिस्सेदारी 2 फीसदी से कम है, उनमें शामिल हैं क्रोएशिया (1।81%), पुर्तगाल (1.55%), इटली (1.49%), कनाडा (1.37%), बेल्जियम (1.30%), लक्जमबर्ग (1.29%), स्लोवेनिया (1.29%) और सबसे कम स्पेन (1.28%)। ये वो देश हैं जिन्हें अमेरिका और नाटो बार-बार याद दिला रहे हैं कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है, तो अपनी जेब ढीली करनी होगी। यानि कुल मिलाकर, अमेरिका को ये कहना कि “कुछ देश सिर्फ सुरक्षा मुक्त में पा रहे हैं”, पूरी तरह गलत नहीं है।

ट्रंप का दबाव: अमेरिका क्यों चाहता है ज्यादा खर्च?

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह कहते आए हैं कि अमेरिका अकेले नाटो की सुरक्षा की कीमत चुका रहा है, जबकि बाकी देश अपना हिस्सा नहीं निभा रहे। ट्रंप की योजना के मुताबिक, नाटो देशों को अपनी GDP का 3.5% सीधे मिलिट्री खर्चों पर और 1.5% साइबर सिक्योरिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे सपोर्ट सिस्टम्स पर खर्च करना होगा। इस दो-स्तरीय प्रस्ताव पर कई देशों ने समर्थन तो किया है, लेकिन साथ ही समयसीमा और संसाधनों को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस डिफेंस बजट बढ़ोतरी के जरिए अपने हथियार उद्योग को मजबूत करना चाहता है। ज्यादा डिफेंस बजट का मतलब है ज्यादा खरीद और ज्यादा ऑर्डर और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं।

किसे मंजूर, किसे ऐतराज?

इस प्रस्ताव को लेकर यूरोप बंट रहा है। जर्मनी, नीदरलैंड और बाल्टिक देश जैसे लिथुआनिया 3।5% खर्च के पक्ष में हैं क्योंकि रूस का खतरा उनके दरवाजे तक आ चुका है। लेकिन स्पेन, इटली और कई अन्य देश इसे अस्पष्टता बढ़ेगी जिससे अमेरिका के प्रभाव को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार 2.1% से ज्यादा रक्षा पर खर्च नहीं कर सकती। उनके मुताबिक हम नाटो की जरूरतों को 2.1% खर्च में पूरा कर सकते हैं। इससे ज्यादा करना संभव नहीं है। दरअसल, स्पेन नाटो का सबसे कम खर्च करने वाला सदस्य है। 2024 में उसका रक्षा बजट GDP का केवल 1.28% था। ऐसे में अचानक 5% खर्च का दबाव उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से भारी पड़ सकता है।

2032 या 2035? समयसीमा पर फंसा पैंच

नाटो की अंदरूनी बहस केवल खर्च की मात्रा पर नहीं, बल्कि समयसीमा पर भी है। कुछ देश चाहते हैं कि ये नया टारगेट 2035 तक लागू किया जाए, जबकि अमेरिका 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। बाल्टिक देश 2030 की बात कर रहे हैं वहीं इटली जैसे देश इसे 10 साल का लंबा प्रोसेस मानते हैं। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे ने बीच का रास्ता सुझाया है कि 2032 तक 3।5% खर्च और बाकी 1।5% में लचीलापन। इस प्रस्ताव पर हैग समिट में मुहर लग सकती है।

क्या बदलेगा समिट के बाद?

अगर नाटो समिट में 5% डिफेंस खर्च का नया टारगेट पास हो जाता है, तो ये नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। इससे यूरोप की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, लेकिन कई देशों की आंतरिक राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। स्पेन जैसे देशों में पहले से ही गठबंधन सरकारें और आर्थिक चुनौतियां हैं, ऐसे में ज्यादा डिफेंस खर्च वहां की सरकारों के लिए गले की हड्डी बन सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन के खिलाफ नाटो की तैयारी और स्पष्टता बढ़ेगी जिससे अमेरिका के प्रभाव को भी मजबूती मिलेगी।

ईरान ने आखिरी वक्त तक नहीं मानी हार, इन 2 फोन कॉल से जाकर रुकी इजराइल से जंग

वॉशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सिफारिश पर ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करवाया है। यह खुलासा मैगजीन न्यूजवीक ने अमेरिकी राजनयिक सूत्रों के हवाले से किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जैसे ही कतर पर मिसाइलें दागीं, वैसे ही कतर के अभीर और प्रधानमंत्री अमेरिका की तरफ देखने लगे। न्यूजवीक ने अमेरिकी राजदूत के हवाले से कहा कि कतर की सिफारिश पर ट्रंप ने मध्यपूर्व के अपने दूत विटकोंफ से बात की। विटकोंफ ने इसके बाद ईरानी समकक्ष को फोन मिलाया।

रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के ऐलान होने तक कतर के अभीर और प्रधानमंत्री एक्टिव रहे। दोनों लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात करते रहे। ईरान ने सोमवार को आधी रात में कतर पर ही मिसाइल अटैक किया था। दोहा के अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने 6 मिसाइल दागे थे। कतर आगे भी हमले का डर सता रहा था। Axios ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जैसे ही विटकोंफ ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन लगाया। वैसे ही विदेश मंत्री ने शर्त रख दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची का कहना था कि इजराइल हमला रोकेंगा, तभी बात बन सकती है। अराघाची के मुताबिक जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी। हमला रोकना भी उसी का काम है। इजराइल हमला रोकता है तब हम भी हमला नहीं करेंगे। फोन पर विटकोंफ ने ईरान को यह भरोसा दिलाया कि इजराइल अगले 24 घंटे बाद हमला नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करने के बाद विटकोंफ ने अपना संदेश व्हाइट हाउस को भेज दिया।

6 नदियों पर कर लेंगे कब्जा... बिलावल भुट्टो दे रहे भारत को युद्ध की धमकी



इस्लामाबाद, एंजेंसी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत को खिलाफ एक बार फिर से ज़हर उगला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत को एक बार फिर से गैदइभभकी दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत अगर सिंधु जल सिंध को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी छह नदियों से पानी लेगा। पाकिस्तान सभी छह नदियों पर अपने देश कि जनता के लिए कब्जा कर लेगा। इसके अलावा पाकिस्तान

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने समूह की वार्षिक आम बैठक के दौरान अमेरिका में समूह के खिलाफ हुए मुकदमों और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर अपनी राय रखी है। गौतम अदाणी ने कहा है कि पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग और एसीसी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी से संबंधित आरोप लगाए थे, लेकिन अदाणी समूह के किसी भी व्यक्ति पर एफसीपीए का उल्लंघन करने या न्याय में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया गया है।

दूसरी ओर पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर बोलते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने का असर ऊर्जा और रसद पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप में आर्थिक आत्मविश्वास डगमगा रहा है और अमेरिका के सामने अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इस शोरगुल के बीच भारत अलग खड़ा रहा और किसी भी अन्य प्रमुख देश की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसइल के हाइफा पोर्ट पर अदाणी की 70% हिस्सेदारी

इस्त्राइल में अदाणी की मौजूदगी का केंद्र हाइफा पोर्ट है, जहां अदाणी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी है जिसे 2023 में इस्त्राइल के गैडेट ग्रुप के साथ साझेदारी में 1।2 बिलियन डॉलर में खरीदा गया है। उत्तरी इस्त्राइल में रणनीतिक रूप से स्थित यह पोर्ट अदाणी पोर्ट्स के वार्षिक कार्गो वॉल्यूम में लगभग 3% का योगदान देता है और इस्त्राएली आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है।

अदाणी समूह के पास बाधाओं से परे सपने देखने की हिम्मत हिन्दवर्ग प्रकरण और अमेरिका में हुए मुकदमों की इशारा करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि हम चुनौतीपूर्ण वर्षों में भी एक ऐसे समूह

के प्रमाण के रूप में खड़े हैं जो बाधाओं से परे सपने देखने की हिम्मत रखता है।

उन्होंने कहा, ‘हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकारात्मकता अक्सर सच्चाई से ज्यादा जोर से गुंजती है। हम कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करते हैं, मैं यह भी दोहराना चाहता हूँ कि हमारा शासन वैश्विक मानकों पर आधारित है।’ गौतम अदाणी ने कहा कि हमारे अनुपालन ढांचे से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हमारे आंकड़े अपनी कहानी खुद बताते हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों से भरे वर्षों में भी, हमने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, अभूतपूर्व वृद्धि और ऐतिहासिक लाभप्रदता देखी।

अदाणी एयरपोर्ट्स को मिला 1 अरब डॉलर का वित्तपोषण

अदाणी समूह की एंविएशन शाखा ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण के लिए वैश्विक निवेशकों से एक अरब डॉलर का वित्तपोषण हासिल किया है। समूह ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया, ‘लेन-देन का नेतृत्व अपोलो द्वारा प्रबंधित फंडों की ओर से किया गया, जिसमें प्रमुख संस्थागत निवेशकों और बीमा कंपनियों के एक समूह ने भाग लिया, जिसमें ब्लैकरोक द्वारा प्रबंधित फंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि शामिल थे। इस डील ने भारत के बुनियादी ढांचे के अवसर और अदाणी एयरपोर्ट्स के परिचालन प्लेटफॉर्म में वैश्विक विश्वास को दर्शाया है।’

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और भारत की सबसे बड़ी निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने अपने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के लिए परियोजना वित्त संरचना के माध्यम से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए।

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीजफायर की घोषणा की।

बड़ा सवाल- जंग में अब आगे क्या?

इजराइल और अमेरिका की कोशिश ईरान के यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने की थी। अमेरिका ने इसी रणनीति के तहत ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाने पर लिया। हालांकि, ईरान का कहना है कि वहां यूरेनियम थे ही नहीं।

द टेलीग्राफ ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक अटैक से पहले लै 400 किलोग्राम यूरेनियम को ईरान ने शिफ्ट कर लिया। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का कहना है कि अभी एक-दो साल तक ईरान परमाणु बम तैयार नहीं करा पाएगा। आगे क्या होगा, यह बहुत कुछ ईरान की अगली रणनीति पर निर्भर करेगा।

गृह मंत्री के बयान पर तिलमिलाया पाकिस्तान

भारत ने UN में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि, “पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।” सिंधु जल सिंध टूटने के पीछे भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ऐसा बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल सिंध को लेकर तनाव बना हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में इस सिंध पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर गृह मंत्री के बयान की आलोचना की। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था।



उपचुनाव की जीत से केजरीवाल को मिली संजीवनी, गुजरात-पंजाब में आप ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता निकल जाने से आम आदमी पार्टी हताश और निराश हो गई थी, लेकिन उपचुनाव में दो सीटें उसके हिस्से में आई हैं। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसने कांग्रेस की राजनीतिक टेंशन बढ़ा दी है। दो साल के बाद गुजरात और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो सकती है?

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता और अपनी सीट गंवाने के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीति सियासी परवान चढ़ी थी। यही वजह थी कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन चार महीने के बाद उपचुनाव में दो सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी कमबैक करने में कामयाब रही है। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दोनों के लिए सियासी



संजीवनी मानी जा रही है।

आप उपचुनाव में दो सीटें जीतने में सफल

पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को 35179 मत हासिल हुए तो कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 24542 वोट मिले। संजीव अरोड़ा 10637 वोटों से जीत दर्ज कर विधायक बन गए हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से लुधियाना पश्चिम सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने में सफलता हासिल की है, जो कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है।

वहीं, गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कादी सीट

बीजेपी और विसावदर सीट आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया को 75942 वोट मिले और बीजेपी के किरीट पटेल को 58388 वोट मिले। आम आदमी पार्टी यह सीट 17554 वोट से जीतने में सफल रही है।

2022 में इस सीट से आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र भाई भयानी विधायक चुने गए थे, लेकिन बीजेपी का दामन थाम लेने के चलते उपचुनाव हुए थे। इसके बाद भी बीजेपी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी से नहीं जीत सकी।

आम आदमी पार्टी के लिए सियासी संजीवनी

दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव में पांच में से दो सीटें जीतना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं

है। लुधियाना पश्चिम सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत सियासी आधार रखा है। इसी तरह से गुजरात की विसावदर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अपने साख का सवाल बना हुआ था, जिसे जीतकर अपना दबदबा को बनाए रखने में सफल रही है। यही नहीं आम आदमी पार्टी के विधायक को अपने साथ मिलाने के बाद भी बीजेपी यह सीट नहीं जीत सकी। इन दोनों सीटों पर जीत आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी मानी जा रही है जो कि आगे के चुनाव में एनर्जी देने का काम करेगी।

दिल्ली में हार के बाद जिस तरह का सियासी माहौल आम आदमी पार्टी के लिए बन गया था और केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े होने लगे थे, उसमें उपचुनाव की दो सीटें जीती है, वो आम आदमी पार्टी के हौसले को बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली की हार के बाद पंजाब में कांग्रेस-बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह के बीच लुधियाना सीट जीतना और बीजेपी के हाथ गुजरात में आम आदमी पार्टी का सीट निकालना बहुत ही अधिक चौकाने वाला है। उपचुनाव में पांच से दो सीटें जीतना सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की वापसी करना का मौका दे दिया है।

जीत के केजरीवाल ने दिया सियासी संदेश

पंजाब और गुजरात में उपचुनाव जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुजरात और पंजाब दोनों ही जगह पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग दोगुने मार्जिन से जीत हुई है। ये दिखाता है कि पंजाब के लोग हमारी सरकार के कामों से बहुत खुश हैं और उन्होंने 2022 से भी ज्यादा वोट दिया है।

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता अब बीजेपी से परेशान हो चुकी है और उन्हें आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई दे रही है। दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ीं। इन दोनों का एक ही मकसद आम आदमी पार्टी को हराना था, लेकिन जनता ने दोनों ही जगह इन दोनों ही दल को पूरी तरह से नकार दिया। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सियासी संदेश दिया कि पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो गुजरात में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सियासी विकल्प मान रहे हैं?

पंढरपुर यात्रा पर ऐसा क्या बोले अबू आजमी, मांगनी पड़ी माफी, भाजपा नेता ने कहा – दफना दिए जाओगे

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी ने वारी यात्रा पर दिए गए विवादस्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से गलतफहमी हुई और वारकरी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आजमी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव पर ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने अपने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का भी आरोप लगाया है।

अबू आजमी अपने बयानों के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। इसके कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है। पिछली बार उन्होंने औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। इसके साथ ही मामला भी दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में विधायक के गुप्ते के बाद आखिरकार अबू आजमी ने माफी मांग ली है, लेकिन भाजपा आध्यात्मिक मोर्चा के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र की अस्मिता से खेलना जारी रखा तो वहीं दफना दिए जाओगे।



माफी मांगते हुए क्या बोले आजमी?

विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने इस मामले में जल्दबाजी करते हुए माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हाल ही में सोलापुर में मेरे द्वारा की गई एक टिप्पणी को लेकर जो गलतफहमियां फैली हैं, मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे वक्तव्य को तोड़मरोड़ कर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। यदि इससे वारकरी समुदाय की धार्मिक भावना आहत हुई हो, तो मैं अपने शब्द पूरी तरह से वापस लेता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। मेरी मंशा कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।

उन्होंने आगे लिखा कि मैं एक समर्पित समाजवादी हूँ और हमेशा से हर धर्म, संस्कृति, सूफी संतों तथा उनकी परंपराओं का आदर करता

आया हूँ। मैं वारी परंपरा का पालन कर रहे सभी वारकरी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके प्रति अपनी सम्मान भावना प्रकट करता हूँ। यह परंपरा महाराष्ट्र की सर्वधर्मीय, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का गौरवपूर्ण हिस्सा है, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ।

उपेक्षित समाज के हक़- सम्मान लड़ाई रहेगी जारी

आजमी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मेरी तरफ से वारी पालखों का उल्लेख केवल मुस्लिम समाज के साथ हो रहे भेदभाव और उनके अधिकारों के संदर्भ में किया गया था। यह किसी प्रकार की तुलना नहीं थी एवं मेरी नीयत और मेरी मांग किसी भी रूप में अनुचित नहीं थी।

उन्होंने कहा कि मेरी केवल इतनी मंशा थी कि सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कर सकूँ कि उसके दोहरे मापदंड अल्पसंख्यक समुदाय के मन में यह भावना न उत्पन्न करें, कि उनके लिए इस देश में अलग कानून हैं। जब की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास।



नताशा स्टेनकोविक ने बोल्ड फोटोशूट से मचाया तहलका, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक अक्सर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं। जी हां, वो आए दिन अपने बोल्ड लुक्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और छा जाती हैं। इसी बीच अब उन्होंने अपनी कुछ ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैस भी हैरान रह गए हैं। तो चलिए उनके नए लुक के बारे में आपको भी बताते हैं।

दरअसल, नताशा स्टेनकोविक ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रही रही हैं। जी हां, अपनी इन तस्वीरों से एक्ट्रेस हर तरफ छा गई हैं। इन तस्वीरों में नताशा ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और ब्लू कलर की डेनिम पहने दिखाई दे रही हैं। मिनिमल मेकअप और खुले बालों में नताशा बेहद स्टनिंग दिख रही हैं। वहीं इस दौरान नताशा ने अपनी जीन्स की चेन खोलकर जमकर पोज दिए। ऐसे में अब उनकी इन तस्वीरों को देखने के बाद नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया है।

जहां कुछ फैस नताशा की फोटोज देखकर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी जीन्स की चेन खुली देखकर उनपर भड़क गए हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। एक दूसरे शब्दस ने कमेंट किया- ये कौन सा पोज है भाई। इसके अलावा, एक यूजर ने लिखा- चढ़ी दिखाने का ट्रेंड बना लिया क्या। इसके अलावा एक यूजर ने कहा- थोड़ी तो शर्म कर लो।



तमिल सिनेमा के अभिनेता श्रीकांत एक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पुलिस ने अभिनेता को तकरीबन आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जहां वो 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। श्रीकांत पर ये कार्रवाई ड्रम्स से जुड़े एक मामले में हुई है।

एक्टर के ड्रम्स लेने की हुई पुष्टि

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकांत के ब्लड सैमल किलपौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए एकत्र किए गए थे। जिसके बाद जांच में अभिनेता के शरीर में नशीले पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि हुई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद सोमवार रात को श्रीकांत को एमोर स्थित 14वें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आवास पर ले जाया गया



और रिमांड पर लिया गया। अब उन्हें 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कल अभिनेता से हुई थी पूछताछ

पूर्व एआईएडीएमके पदाधिकारी टी प्रसाद को हिरासत में लिए जाने के बाद सोमवार को नुंगमक्कम पुलिस थाने में

साथ काम करनामेरे लिए यकीनन एक शानदार ट्रीट है। वह इस शैली के उस्ताद हैं और मेरे लिए यह एक बड़ा सीखने का अनुभव और खुशी देने वाला अनुभव होने वाला है।

निर्देशक वरुण कहते हैं, यह कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। हम पंकज और अदिति को साथ लाने के लिए

बेहद उत्साहित हैं। वरुण इससे पहले सलमान खान की भारत और सुल्तान जैसी फिल्मों के लेखक रहे हैं। पारिवारिक मनुरंजन उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फीचर फिल्म होगी, जिससे अली अब्बास जफर बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़े हैं। उधर जहां पंकज फिल्म मेट्रो।इन दिनों के प्रचार में जुटे हैं, वहीं अदिति वेव सीरीज ओ साथी रे में नजर आएंगी।

ड्रग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया ये साउथ एक्टर, कोकीन खरीदने का लगा आरोप



अभिनेता से पूछताछ की गई। पुलिस को शक है कि प्रसाद ने 46 वर्षीय श्रीकांत और एक अन्य अभिनेता को कोकीन की आपूर्ति की है। इस पूरे मामले में जांच के बाद अब ये कदम उठाया गया है।

11 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त होने की खबर

पिछले सप्ताह नुंगमक्कम पुलिस ने सलेम के प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया था और उससे मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने घाना के जॉन नामक व्यक्ति को राज्य के होसुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उनके पास से करीब 11 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया।

कई तमिल फिल्मों में नजर आ चुके हैं श्रीकांत

श्रीकांत के करियर की बात करें तो वो पिछले 26 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 1999 में टीवी शो जन्नाल – मरवू कव्थैगल से अपना करियर शुरू किया था। श्रीकांत ने काना कंडेन, ओरु नाल कनवु, बाम्बारा कन्नले, मनासेल्लम, वर्णजलम, मकरी पूक्कल, ईस्ट कोस्ट रोड, पू, सधुरंगम और नानबन जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वो आखिरी बार तमिल फिल्म 'कोनजम कथल कोनजम मोथल' और तेलुगु फिल्म 'एरराचेरा' में नजर आए थे।

